

समस्या कणवधाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-13

अंक-21

हरिद्वार, मंगलवार, 15 सितम्बर, 2026

मूल्य-दो रूपया मात्र

पृष्ठ-8

उत्तराखण्ड कैबिनेट में लगी अहम प्रस्तावों पर मुहर



देहरादून, संवाददाता । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद, कारागार प्रशासन, न्याय और पर्यटन विकास से जुड़े 10 मुख्य प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। सबसे बड़ा लाभ राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एमबीबीएस इंटरन्स और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखरने वाले खिलाड़ियों को मिला है।

मेडिकल इंटरन्स का वजीफा बढ़ा, 243 खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
राज्य के पांच प्रमुख राजकीय मेडिकल कॉलेजों—देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और हरिद्वार—में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर रहे छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट

ने इंटरन्स को मिलने वाले मासिक वजीफे को 17,000 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, खेल नीति 2021 के तहत राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधा प्रोत्साहन देने का फैसला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों को खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिया जाएगा। इसी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित कर लेवल-6 के अपर सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 नए पद सृजित किए गए हैं।

शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में इजाफा और लीगल मेट्रोलाजी नियमों का सरलीकरण
अदालती व्यवस्था में राज्य सरकार का

पक्ष मजबूती से रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सात सदस्यीय समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल स्थित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय और विभिन्न जिला व अधीनस्थ अदालतों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों में

पुनर्निर्धारण यानी फीस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। कारोबार को आसान बनाने (Ease of Doing Business) के केंद्र सरकार के 'डिरेक्शन फेज-2' के तहत उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2012 में संशोधन

**—उत्तराखण्ड कैबिनेट के बड़े फैसले : एमबीबीएस इंटरन्स का वजीफा बढ़ा, खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरियां
—मेडिकल इंटरन्स को अब मिलेंगे 25 हजार, आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स कोटा भी मंजूर**

कर नए नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं। इससे नापतौल लाइसेंसिंग प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। साथ ही, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

मसूरी रोप-वे, ईएसआई अस्पताल और जेल प्रशासन में बदलाव
पर्यटन और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर देहरादून के पुरकूल गांव से मसूरी (लाइब्रेरी चौक) तक बनने वाले महात्माकांक्षी रोप-वे प्रोजेक्ट को गति दी गई है। रोप-वे के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण के लिए गढ़वाल सभा मसूरी की पूर्व लीज भूमि अधिग्रहित की

गई थी। इसके एवज में गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग वाली भूमि में से 972 वर्ग मीटर जमीन गढ़वाल सभा को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में हरिद्वार स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के समीप चिह्नित 15 एकड़ भूमि नए ईएसआई अस्पताल के निर्माण हेतु आवंटित कर दी गई है। वहीं, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सुधारात्मक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अपर महानिरीक्षक (AIG) कारागार का एक नया पद सृजित कर नियमावली 2026 के प्रख्यापन को सहमति दी गई।

कुंभ मेला-2027 के लिए 700 करोड़ से अधिक की लागत की योजनाओं पर तेजी से चल रहा काम

हरिद्वार, संवाददाता । आगामी कुंभ मेला-2027 को भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए चार जिलों में फैले 32 सेक्टरों वाले मेला क्षेत्र में अवस्थापना विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कुंभ से जुड़े 126 कार्यों के लिए अब तक लगभग 709.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है और इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। वर्षाकाल समाप्त होते ही निर्माण कार्यों को और गति देते हुए युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी मेला प्रशासन ने कर ली है।

मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन स्थित सीसीआर सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कुंभ मेला की तैयारियों, निर्माण कार्यों और आगामी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला-2027 से जुड़े सभी प्रमुख कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार चल रहे हैं और सभी कार्य तय समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बड़े निर्माण कार्य शीघ्र पूरे होने की स्थिति में हैं, जबकि सड़क एवं अन्य अवस्थापना विकास की योजनाओं को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। मेलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के लिए केवल कार्य पूरा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करना लक्ष्य है। कुंभ की तैयारियों में सुविधा, सुरक्षा,



सुगमता और सुव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार से स्वीकृत एवं अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत सड़क, पुल, घाट, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, स्वच्छता एवं सैनिटेशन, यातायात, सौंदर्यीकरण सहित श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। इनमें अधिकांश कार्य स्थायी प्रकृति के हैं, जिनका लाभ कुंभ के बाद भी हरिद्वार को मिलता रहेगा।

श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए पैदल यात्रियों के अनुकूल फुटपाथ विकसित करने की पहल की जा रही है। घाटों के विस्तार एवं सुधार के साथ पैदल आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ

नगरी को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के साथ आंतरिक सड़कों और गलियों के सुधार तथा बेहतर रखरखाव की भी व्यवस्था की जा रही है। यातायात के सुचारू संचालन के लिए पांच बड़े पुलों के निर्माण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना कार्य प्रगति पर हैं। मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश से लेकर घाटों तक पहुंचने और वापस लौटने तक बेहतर अनुभव मिले, इसी सोच के साथ प्रमुख मार्गों से लेकर आंतरिक गलियों तक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। सड़क, फुटपाथ, पुल, घाट और यातायात व्यवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़कर समग्र रूप से विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार के आध्यात्मिक स्वरूप को और निखारने के लिए सौंदर्यीकरण के कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

अव्यवस्थाओं के खिलाफ सप्तरहण में कांग्रेस ने किया डमरू, चिमटे बजाकर प्रदर्शन

हरिद्वार । सप्तरहण क्षेत्र में अधूरे नाला निर्माण और सीवर लीकेज से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने डमरू और चिमटे को बजाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द अधूरे नाले का निर्माण पूरा करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान अशोक शर्मा ने कहा कि नाला आधा बनाकर छोड़ दिया गया जिसके कारण सारा पानी सड़क पर बह रहा है। यात्री बाहुल्य क्षेत्र में दिन रात बाहर से आने वाला श्रद्धालु मार्ग का प्रयोग करता है लेकिन शासन प्रशासन जनहित की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। श्रद्धालुओं को गंदे दूषित सीवर के पानी में से होकर निकलना पड़ता है। इससे संक्रमित बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि पार्श्व, मेयर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक

भाजपा के हैं उसके बाद भी क्षेत्र की हालत खराब है। पहले भी कुंभ हुए हैं लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। कुंभ के नाम पर बंदरबांट हो रहा है। सन्नी मल्होत्रा, अनिल ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र को नरक बनाकर रख दिया है। सुबह सुबह ही सीवर का दूषित पानी सड़क पर बहता है जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। स्थानीय पार्श्व द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। भाजपा शासन में जनता परेशान है। समस्या काफी समय से बनी हुई है। स्थानीय विधायक ने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जिसके कारण लोगों को गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन में पार्श्व सुनील कुमार, रणवीर शर्मा, रवि बाबू शर्मा, अनंत पांडे, हरद्वारी लाल, करण राणा, सोम त्यागी, विकास चंद्रा आदि उपस्थित रहे।

सम्पादकीय



सुरक्षित भारत की जरूरत

भारत में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तालाब और कुएं सूख रहे हैं तथा खेती और पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे समय में पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। इसी सोच के साथ ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान शुरू किया गया है। 6 सितंबर 2024 को शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बचाना, भूजल स्तर बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर पानी के स्रोतों को मजबूत करना है। इसके तहत कम खर्च में जल संरक्षण की संरचनाएं बनाने, पुराने और बंद पड़े नलकूपों को फिर से उपयोगी बनाने तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार जल संरक्षण के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें सरकार के साथ आम जनता, पंचायतें, सामाजिक संगठन और कंपनियां भी जुड़ सकती हैं। इसका आधार तीन ‘सी’ हैं—समुदाय, कंपनियों का सामाजिक दायित्व और लागत। यानी समुदाय की भागीदारी, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी और कम खर्च में जल संरक्षण। इससे जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना न बनाकर जन-अभियान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में बड़ी संख्या में जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। पहले चरण के तहत मई 2025 तक देश में 27 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं। इसके बाद जून 2025 में दूसरा चरण शुरू किया गया। मई 2026 तक डेढ़ करोड़ से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जा चुकी थीं। 3 सितंबर 2026 तक यह संख्या एक करोड़ 58 लाख से अधिक हो गई। यह आंकड़ा बताता है कि देश में जल संरक्षण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन केवल संरचनाएं बना देना ही काफी नहीं है। उनका सही स्थान पर बनना, नियमित रखरखाव और सही उपयोग भी जरूरी है। यदि बारिश का पानी इन संरचनाओं तक पहुंचे ही नहीं या कुछ वर्षों बाद वे मिट्टी और कचरे से भर जाएं तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। भारत में पानी बचाने की परंपरा पहले से रही है। गांवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और छोटे बांध लोगों की जरूरत पूरी करते थे। हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में आज भी पुराने जल स्रोत इसकी याद दिलाते हैं। आधुनिक विकास के दौरान हमने इन स्रोतों की उपेक्षा की और भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब समय है कि पुरानी समझ को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी को ‘वर्षा जल संचयन’ अभियान से भी जोड़ा गया है। जून 2026 में इसे ‘जल शक्ति अभियान—वर्षा जल संचयन’ के साथ मिलाकर नया रूप दिया गया। इसका सीधा संदेश है—बारिश की हर संभव बूंद को व्यर्थ बहने से रोकना और उसे जमीन में पहुंचाना।

समझौते कृषक हितों के खिलाफ

कहना कठिन है कि किसानों का संघर्ष कितना प्रभावी होगा। लेकिन यह साफ है कि किसान- मजदूर वर्गों में वर्तमान आर्थिक नीतियों के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत का अहसास लगातार गहरा रहा है। किसान संगठन फिर आंदोलन की राह पर हैं। गुजरे दस अगस्त को उन्होंने ‘जेल भरो’ मुहिम चलाई। अब वे सांसद और विधायकों सहित सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना मांग-पत्र सौंप रहे हैं। उनकी मांगों और घोषित रणनीति पर गौर करें, तो संकेत मिलता है कि अकेले लड़ाई लड़ने की अपर्याप्तता का उन्हें अहसास हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने संघर्ष में खेतिहर और शहरी मजदूरों को शामिल करने के साथ-साथ अपने मांग-पत्र में संघीय व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की आम दिशा से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया है। उनका आरोप है कि केंद्र ‘कॉरपोरेट केंद्रित’ नीतियों को आगे बढ़ा रहा, जिसकी मार किसान, मजदूर एवं आम मध्यम वर्ग पर पड़ी है। इसलिए अपने को कृषि क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मांग-पत्र को आजीविका, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के बड़े दायरे से जोड़ा है। उनकी एक प्रमुख मांग है कि कर राजस्व का राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से की मात्रा 31 से बढ़ा कर 50 फीसदी की जाए। मोर्चा का तर्क है कि कृषि संकट हल करने, कृषि आधारित औद्योगीकरण और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलना अनिवार्य है। मांग पत्र में भारत- अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता पर विरोध जताया गया है। साथ ही हाल में हुए तमाम मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने की मांग की गई है। किसान संगठनों का दावा है कि ये सारे समझौते कृषक हितों के खिलाफ हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्यापक कृषि कर्ज माफी, 200 दिन काम की गारंटी और 700 रुपये प्रति दिन मजदूरी के प्रावधान के साथ मनरेगा की बहाली, चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, भूमि अधिकारों के संरक्षण, और बिजली निजीकरण एवं बीज विधेयकों की वापसी की मांग भी दोहराई गई है। फिलहाल, कहना कठिन है कि इस बार अधिक बड़ा मोर्चा बनाकर किसानों ने संघर्ष का जो एलान किया है, वह असल में कितना प्रभावी होगा। लेकिन यह जरूर है कि किसान- मजदूर वर्गों में आर्थिक नीतियों की वर्तमान दिशा के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत का अहसास लगातार गहराता जा रहा है।

हिंदी दिवस: उत्सव नहीं, भाषा के भविष्य का संकल्प

- डॉ. सत्यवान सौरभ

हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस हमारे संवैधानिक इतिहास, भाषायी विविधता और सांस्कृतिक स्मृति से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान लागू होने के बाद इस निर्णय को अनुच्छेद 343 में स्थान मिला। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

लेकिन हिंदी दिवस का अर्थ केवल इतना नहीं होना चाहिए कि इस दिन हिंदी के महत्व पर भाषण दिए जाएँ, कविताएँ सुनाई जाएँ और सरकारी कार्यालयों में हिंदी सप्ताह या पखवाड़े आयोजित कर औपचारिकता पूरी कर ली जाए। असली सवाल यह है कि हिंदी हमारे जीवन, शिक्षा, प्रशासन, न्याय, विज्ञान, तकनीक और रोजगार की भाषा कितनी बन पाई है। यदि हिंदी का सम्मान समारोहों और घोषणाओं तक सीमित है, तो हिंदी दिवस हमें उत्सव से अधिक आत्ममंथन का अवसर देता है। सबसे पहले यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह अंतर केवल संवैधानिक शब्दावली का विषय नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संवेदना का भी प्रश्न है। भारत की पहचान उसकी भाषायी विविधता से निर्मित होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, मैथिली और अनेक अन्य भारतीय भाषाएँ समाज की स्मृतियों, अनुभवों और सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्ति देती हैं। इसलिए हिंदी का विकास इन भाषाओं के विरोध में नहीं, बल्कि उनके साथ संवाद और सहयोग के माध्यम से होना चाहिए।

हिंदी को यदि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क की भाषा बनने का अवसर मिला है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। हिंदी संवाद का पुल बने, प्रभुत्व का माध्यम नहीं। किसी भी भाषा का विस्तार तभी सहज और स्वीकार्य होता है, जब उसमें सम्मान, संवेदनशीलता और समावेश की भावना हो।

हिंदी दिवस पर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में निबंध-लेखन, भाषण, वाद-विवाद, कविता-पाठ, प्रश्नोत्तरी और पुरस्कार-वितरण जैसे कार्यक्रम होते हैं। इन आयोजनों का अपना महत्व है और वे भाषा के प्रति उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन हिंदी का वास्तविक विकास इन कार्यक्रमों के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। हिंदी को समारोहों की भाषा से आगे बढ़ाकर प्रयोग और ज्ञान की भाषा बनाना समय की आवश्यकता है।

आज भी सरकारी वेबसाइटों, शोध-सामग्रियों और अनेक आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और नवीन शोध-सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है। विज्ञान, चिकित्सा, कानून, प्रबंधन और सूचना-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हिंदी सामग्री उपलब्ध तो है, लेकिन उसकी मात्रा, गुणवत्ता और अद्यतन स्वरूप को अभी और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने के लिए केवल अनुवाद पर्याप्त नहीं होगा। मौलिक लेखन, आधुनिक शब्दावली, विषय-विशेषज्ञों की



भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण संपादन भी जरूरी है। किसी अंग्रेजी पुस्तक का कठिन और यांत्रिक अनुवाद विद्यार्थियों को हिंदी के करीब नहीं लाता। ज्ञान तभी जनमुलभ होगा, जब उसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और विषयानुकूल हो। भाषा और शिक्षा का संबंध भी अत्यंत गहरा है। जिस भाषा में बच्चा सोचता और अनुभव करता है, उसी भाषा में उसे जटिल विषयों को समझने का बेहतर अवसर मिलता है। इसके बावजूद भारत में भाषा-शिक्षा का प्रश्न अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और रोजगार की चिंता से जुड़ जाता है। अंग्रेजी का ज्ञान आज के वैश्विक और रोजगारपरक परिवेश में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा को कमतर माना जाए।

हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने अक्सर दोहरी चुनौती होती है। एक ओर उन्हें अपनी भाषा में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन-सामग्री नहीं मिलती, दूसरी ओर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी शब्दावली के कारण अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान किसी एक भाषा को हटाकर नहीं, बल्कि मजबूत बहुभाषी शिक्षा-व्यवस्था विकसित करके किया जा सकता है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी में विज्ञान, समाज-विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र और तकनीक की उच्चस्तरीय सामग्री तैयार होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हिंदी में शोध करने, डिजिटल सामग्री तैयार करने, पत्रकारिता करने और नए विचार व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। हिंदी को केवल परीक्षा की भाषा नहीं, बल्कि चिंतन और नवाचार की भाषा बनाना होगा। डिजिटल युग ने हिंदी के सामने नई संभावनाएँ भी खोली हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार के साथ समाचार-पोर्टल, वीडियो मंच, पॉडकास्ट, ब्लॉग और सोशल मीडिया पर हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ी है। करोड़ों लोग हिंदी में समाचार पढ़ते, मनोरंजन सामग्री देखते और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह हिंदी के लिए बड़ा अवसर है। लेकिन डिजिटल हिंदी के सामने चुनौतियाँ भी हैं। रोमन लिपि में हिंदी लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे त्वरित संवाद तो संभव होता है, लेकिन देवनागरी लेखन की आदत कमजोर पड़ने की आशंका भी रहती है। सोशल मीडिया पर भाषायी अशुद्धियों, अधूरी जानकारी और सनसनीखेज अभिव्यक्तियों का प्रसार भी चिंता का विषय है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान दौर में हिंदी को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और भी जरूरी हो गया है। हिंदी

में बेहतर अनुवाद-सॉफ्टवेयर, वाक-पहचान प्रणालियाँ, डिजिटल शब्दकोश, ई-पुस्तकालय और ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने होंगे। भाषा-प्रौद्योगिकी में निवेश के बिना हिंदी डिजिटल भविष्य में केवल सामग्री की उपभोक्ता बनकर रह सकती है। उसे सृजन, ज्ञान और नवाचार की भाषा बनाने के लिए संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं। हिंदी का भविष्य सरकारी आदेशों से अधिक युवाओं की पसंद और प्रयोग से तय होगा। युवा हिंदी में तभी लिखेंगे और पढ़ेंगे, जब उन्हें इसमें आधुनिक विषयों, रोजगार और अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दिखाई देंगे। इसलिए हिंदी को केवल अतीत के गौरव तक सीमित रखने के बजाय वर्तमान की जीवंत भाषा बनाना होगा। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और सिनेमा को बेरोजगारी, जलवायु संकट, लैंगिक असमानता, प्रवासन, डिजिटल निजता, मानसिक स्वास्थ्य और बदलते पारिवारिक संबंधों जैसे समकालीन प्रश्नों से संवाद करना होगा। नई पीढ़ी की भाषा, उसके अनुभव और उसकी बेचैनी अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों में दिखाई देनी चाहिए। जो भाषा अपने समय की समस्याओं को व्यक्त नहीं करती, वह धीरे-धीरे औपचारिक होकर जीवन से दूर हो सकती है।

आज हिंदी में ब्लॉगिंग, स्वतंत्र पत्रकारिता, पटकथा-लेखन, विज्ञापन, अनुवाद, पॉडकास्ट और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएँ मौजूद हैं। इन क्षेत्रों को संस्थागत समर्थन देकर हिंदी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हिंदी के विकास के लिए नीति के स्तर पर भी ठोस पहल आवश्यक है। सरकारी सेवाओं और न्यायिक प्रक्रियाओं में सरल तथा स्पष्ट हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा और तकनीकी विषयों की गुणवत्तापूर्ण सामग्री हिंदी में तैयार होनी चाहिए। अनुवादकों, संपादकों और विषय-विशेषज्ञों को बेहतर अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी के साथ सभी भारतीय भाषाओं के अध्ययन और प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डिजिटल मंचों के लिए सरल, आधुनिक और मानकीकृत हिंदी विकसित करने के साथ सरकारी वेबसाइटों और सार्वजनिक सेवाओं को बहुभाषी तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाना चाहिए। हिंदी में मौलिक शोध, पत्रकारिता और साहित्यिक प्रयोगों को आर्थिक तथा संस्थागत सहयोग मिलना भी जरूरी है। वर्ष 2026 में हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14 सितंबर को किया जा रहा है। ऐसे अवसर को केवल प्रशासनिक प्रयोग की चर्चा तक सीमित रखने के बजाय हिंदी के व्यापक सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी भविष्य पर विचार का मंच बनाया जाना चाहिए।

देवभूमि ने वीरभूमि बनकर देश को दिए अदम्य साहसी और वीर सेनानी : नवीन

हल्द्वानी । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि सैनिक देश के सुख, शांति और स्वतंत्रता के आधार हैं। कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हल्द्वानी के बेरीपड़ा स्थित पवित्र 'अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर' में विधिवत पूजा-अर्चना कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया और शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरान्त उन्होंने हल्द्वीचौड़ बूथ भाजपा अध्यक्ष राकेश चंद्र आर्य के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कर्नल अजय कोटियाल, राम सिंह कैड़ा, सुबेदार मेजर बहादुर सिंह मेहरा, कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी, कैप्टन गंधीर सिंह धामी, शमशेर सिंह बिष्ट सहित अन्य नेतागण व पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। नितिन नवीन ने कहा कि सैनिकों ने इस देश के लोगों को सुख, शांति और स्वतंत्रता के साथ जीवन दिया है, मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी सैनिक बंधुओं को प्रणाम, अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज जब मैं उनके बीच आया हूँ तो सैनिकों के जन्मे को सलाम करता हूँ। जब मुझे सरहद पर जाने और उन सीमाओं को देखने का मौका मिला, जहाँ सैनिक भाई बिना धूप, पानी और बरसात की चिंता किए निरंतर देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो मुझे लगा कि आज अगर 140 करोड़ देशवासी सुख और शांति से रहते हैं, तो इसका एकमात्र कारण वही सैनिक है, जो सरहद पर खड़ा



होकर देश को सुरक्षित बनाए रखता है। सैनिकों के रिटायर होने पर 'पूर्व सैनिक' लिखा जाता है, लेकिन उनका जन्मा, रूख, राष्ट्रप्रेम और हमेशा जीवंत रहने वाली जवानी कभी रिटायर नहीं हो सकती। वे हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। आज सुबह मैंने हल्द्वानी की ऐतिहासिक धरा पर आकर मां काली चौड़ के पावन चरणों में शीश झुकाया। मैं मां नैना देवी के जागृत शक्तिपीठ, सिद्ध कैंची धाम के नीम करौली बाबा और घोड़ाखाल में विराजते कुमाऊं के न्याय के देवता गोलू देवता की पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। जिस भूमि की रक्षा स्वयं देव करते हैं और जो वीरों के बलिदान से पवित्र हुई हो, वहां कोई अन्याय नहीं हो सकता और गोलू देवता के आशीर्वाद से उत्तराखंड और भारत हमेशा आगे

बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुमाऊं रेजीमेंट के ध्येय वाक्य 'पराक्रमो विजयते' (पराक्रम ही विजयी होता है) का जिक्र करते हुए कहा कि यह हर सैनिक को ऊर्जा देने का काम करता है। मैं 1962 के रेजांग ला में 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह और जवानों के आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ने तथा एक इंच भी पीछे न हटने के पराक्रम को नमन करता हूँ। इस देश की मिट्टी ने ऐसे यशस्वी सैनिक पैदा किए हैं। 1967 में घोड़ाखाल में खोले गए सैनिक स्कूल से 800 से अधिक छात्र सैनिक अफसर बनकर निकले हैं और इसी भूमि ने भारत को पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी दिया है। आज मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

सैनिक परिवार के बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड को 'चार धाम' के साथ-साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'पंचम धाम' (वीर सैनिकों की भूमि) की संज्ञा देना बहुत ही अभिनंदन योग्य है। नवीन ने कहा कि 2011 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था और राष्ट्रीय एकता यात्रा के सिलसिले में कश्मीर के लाल चौक गया था, तो वहां पाकिस्तान का झंडा फहराता देख मेरा सिर शर्म से झुक गया था। परंतु 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सोच में परिवर्तन आया और आज लाल चौक पर लहराता तिरंगा हर भारतवासी और सैनिक को गर्व और ऊर्जा देता है। मैंने 2012 में तवांग की 'शहीद श्रद्धांजलि यात्रा' के दौरान बोमला सीमा पर कच्ची सड़कों की स्थिति देखी थी। उस समय फौजियों और स्थानीय लोगों ने मुझे बताया था कि तत्कालीन सरकार को भय था कि सड़क बनाने से चीन कहीं 1962 की तरह दोबारा सीमाओं तक न पहुंच जाए। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2017 तक भारत की सीमाओं तक पक्की सड़कें बन गईं, जो नेतृत्व की सोच में बदलाव और सैनिकों का मनोबल ऊंचा उठाने को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मन इसी देवभूमि और वीरभूमि में बसता है और वे दिवाली-होली सैनिकों के बीच जाकर मनाते हैं। उन्होंने सीमांत गांवों को 'अंतिम गांव' की जगह 'प्रथम गांव' मानने की सोच में बदलाव की चर्चा की और 46 वर्षों से लंबित 'वन रैंक वन पेंशन' को 7 नवंबर 2015 को लागू करने का कार्य किया। नवीन ने कहा कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिक परिवारों की समस्याओं

के समाधान और योजनाओं के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों के समय परमाणु शक्ति बनने या रक्षा बजट बढ़ाने में झिझक थी, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को परमाणु शक्ति बनाया। आज भारत रक्षा उत्पादन और निर्यात में आत्मनिर्भर हो रहा है, जहां सर्वाधिक 1.78 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हुआ है और रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 'चार धाम ऑल वेदर रोड', दिल्ली में बने 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' में 25,942 सैनिकों के नाम अंकित होना और देहरादून में बन रहे 'सैन्य धाम' तथा 1,845 वीर शहीदों की मूर्तियां उनके गांवों में लगाने के राज्य सरकार के फैसले सराहनीय हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सैनिक परिवार के युवाओं को तो सरहद की अनुभूति होती रहती है, क्योंकि वे उसी सैनिक परिवार में जन्मे हैं। लेकिन देश में जो युवा रहते हैं, उन्हें भी कभी-कभी सरहद पर जाकर देखना चाहिए कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में खड़ा रहता है। जब मैं उस समय की चर्चा कर रहा था, तो मेरे अंदर यह भाव आया कि आने वाले समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी 'सरहद का दर्शन' करने की कोई योजना बने, ताकि हमारी युवा पीढ़ी सरहद पर जाकर केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि हमारे सैनिकों की भावनाओं और सरहद के महत्व को भी समझ सके। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में 'सरहद का दर्शन' कार्यक्रम भी बने, ताकि हमारी युवा पीढ़ी उससे जुड़ सके।

प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जायेगा : मुख्यमंत्री



देहरादून ,संवाददाता । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार को केंद्र में रखते हुए नागरिकों को 'विकसित भारत 2047' के संकल्प से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभियान के अंतर्गत 11 प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, लाभार्थियों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव और लाभार्थियों की कहानियों को भी प्रमुखता से सामने लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के केन्द्र, गैस वितरण केंद्रों, राशन दुकानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, गंगा तट, आदि पर दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक कार्यक्रम किए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज, बांध/पुल, अमृत सरोवर, जन

औषधि केंद्र जैसे स्थलों पर भी सामूहिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा' के अंतर्गत प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 'विकसित भारत' के संकल्प तथा 25 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित चित्रकला, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चयनित चित्र विद्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे तथा अभिभावकों और नागरिकों को भी इन प्रदर्शनियों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमो सेवा-अनकही कहानियां के माध्यम से देश की उपलब्धियों पर आधारित नाटकों का विद्यालयों में मंचन किया जाएगा। साथ ही आंगन मिलन सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों, अभिभावकों, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं की सहभागिता से गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मातृ-बाल स्वास्थ्य, पोषण तथा मातृ-शिशु कल्याण से संबंधित जानकारी पर विशेष जोर रहेगा। अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा की कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव को सामने लाया जाएगा। भाषण, चित्रकला और कहानियों के माध्यम से इन बदलावों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। एवं 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' के तहत किसी प्रमुख चौराहे पर 'विकसित भारत 2047' से संबंधित कलश की स्थापना प्रस्तावित है। कलश यात्रा के साथ साइकिल एवं बाइक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा : मेरा योगदान कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, शिक्षण कार्य तथा अन्य समाजोपयोगी सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

इसका उद्देश्य नागरिकों को अभियान में सक्रिय भागीदार बनाना है। एवं सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर एवं बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के रंग, राष्ट्र के संग कार्यक्रम में रंगोली के माध्यम से विकसित भारत 2047 की दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जाएगा। एवं सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों को जोड़कर उनसे वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्या-विवरणियां प्राप्त की जाएंगी। दृढ़दृष्टि, दृढ़दृष्टि एवं विशेषज्ञों को ज्यूरि/मैंटर के रूप में जोड़ने तथा चयनित नवाचारों को संरक्षण, मार्गदर्शन एवं परीक्षण की सुविधा देने की परिकल्पना है।

अनुमोदन, परीक्षण एवं नियामकीय सहयोग के लिए आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सेवा संवाद के तहत सेवा और सुशासन के विषय पर जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद किया जाएगा। अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित फोटो, वीडियो, लाभार्थियों के अनुभव तथा सकारात्मक बदलाव की कहानियों को मोडिया के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल भाव सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को केवल प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सेवा, संवाद, नवाचार और जनभागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत 2047' के संकल्प का सक्रिय सहभागी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड राज्य से विशेष लगाव है।

लोक भवन में आयोजित हुआ 'एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज' कार्यक्रम



देहरादून । लोक भवन में बुधवार को नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत 'एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में 'नशा मुक्त उत्तराखण्ड हेतु देहरादून घोषणा-पत्र' भी जारी किया गया। यह घोषणा-पत्र प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों में आम लोगों की भागीदारी और ठोस कदम उठाने पर जोर देता है। इसमें युवाओं को नशे से दूर रखने में परिवार की भूमिका मजबूत करने, नशे के आदी लोगों

के उपचार एवं पुनर्वास तथा समाज की भागीदारी बढ़ाने सहित दस प्रमुख संकल्प शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उत्तराखण्ड को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों को और मजबूत करना है।

कार्यक्रम में 'व्यसन मुक्त, सशक्त शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण' विषय पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा का संचालन अनूप नौटियाल ने किया। इसमें दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सीआईएमएस ग्रुप ऑफ कॉलेज एवं सजग इंडिया के अध्यक्ष ललित जोशी, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. संजय जसोला तथा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून के अध्यक्ष डॉ. विजय धस्माना ने प्रतिभाग किया।

महिला सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता जरूरी

हरिद्वार । महिला सशक्तीकरण तभी संभव है, जब महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति समाज जागरूक हो और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। यह बात एसएमजेएन पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। छात्राओं को निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कॉलेज में इनर व्हील क्लब, हरिद्वार के सहयोग से छात्राओं के लिए गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के बचाव, समय पर जांच और एचपीवी टीकाकरण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. डॉ. सुनील कुमार बत्रा और मुख्य वक्ता डॉ. नीता मेहरा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं आईक्यूएसी अध्यक्ष डॉ. संजय माहेश्वरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इनर व्हील क्लब के सामाजिक योगदान की सराहना की। मुख्य वक्ता डॉ. नीता मेहरा ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण, बचाव और एचपीवी वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से अपने आसपास के लोगों को भी इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया। डॉ. ज्योति और डॉ. अमिता मल्होत्रा की ओर से पूछे गए सवालों के डॉ. नीता मेहरा ने विस्तार से जवाब दिए। अंत में डॉ. रुचिता सक्सेना ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति की सदस्य डॉ. पूर्णिमा सुंदरियाल, डॉ. अनुरिषा, डॉ. सरोज शर्मा, ऋचा मिनोचा और डॉ. पल्लवी राणा का विशेष योगदान रहा।

डेंगू-मलेरिया रोकथाम को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने ली बैठक

हरिद्वार । डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम को लेकर नगर निगम ने निगरानी और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम सभागार में हुई समीक्षा बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और लार्वा जांच बढ़ाने पर जोर दिया गया। नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन कार्की की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, लार्वा की जांच करने और जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद नगर निगम की टीम ने निगम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। कूलर का पानी नियमित रूप से बदलने और मच्छरों की रोकथाम के लिए जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया। नगर निगम की ओर से लोगों को तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई। बैठक में मुख्य सफाई निरीक्षक विकास चौधरी, संजय शर्मा, श्रीकांत, विकास कुमार, मनोज कुमार, सुनील, अर्जुन कुमार तथा सफाई निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, धीरेंद्र सेमवाल, अनिल कुमार, आकाश, रूपाली, मोहित, राहुल, प्रशांत और विनय कुमार मौजूद रहे।

विकास के साथ प्रकृति का संतुलन जरूरी : करौली शंकर महाराज

हरिद्वार । हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के संतुलन की कीमत पर नहीं। यह बात हिमालय दिवस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज ने मिश्रीमठ में पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमालय सुरक्षित रहेगा तो नदियां सुरक्षित रहेंगी और नदियों के संरक्षण से खेत, जंगल और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने साधकों के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से देश-विदेश में जुड़े साधकों को हिमालय संरक्षण की प्रतिज्ञा दिलाई और प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने का आह्वान किया। करौली शंकर महाराज ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि और भूकंप जैसी घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। नेपाल में हाल में हुई प्राकृतिक त्रासदी से भी सबक लेने की जरूरत है। जंगलों की कटाई, जलस्रोतों का दोहन और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी आपदा के खतरे को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में विकास योजनाएं स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। हिमालय संरक्षण के लिए जंगलों और जलस्रोतों को बचाना सबसे जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण को केवल हिमालय दिवस तक सीमित न रखते हुए विशेष अवसरों पर पौधरोपण कर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि करौली शंकर धाम के स्वयंसेवक देशभर में 11 लाख पौधे लगाएंगे। डॉ. उमेश सचान ने कहा कि पौधों के रोपण और संरक्षण के लिए देशभर में पौधा एंबुलेंस भी चलाई जाएगी। इस अवसर पर समाजसेवी अनिरुद्ध भाटी, नितिन दास, अनिरुद्ध शर्मा, मनीष कुमार, संतोष सिंह, मौली स्वामी, परमेश्वर समेत सैकड़ों अनुयायी मौजूद रहे।

भीमगोड़ा कुंड के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण को मिलेगी नई पहचान, एचआरडीए को शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश

-कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका ने किया विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण
-रोड़ी बेलवाला में जनसुविधाओं, घाटों और आस्था पथ के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
-दूधाधारी चौक-ज्वालापुर सड़क के नवीनीकरण के कामों में सभी हितबद्ध लोगों के सुझावों को प्राथमिकता



हरिद्वार । कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने के साथ ही हरिद्वार की पौराणिक एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर मेला प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने पौराणिक भीमगोड़ा कुंड के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का जिम्मा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को सौंपते हुए कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

मेलाधिकारी सोनिका ने भीमगोड़ा क्षेत्र का भ्रमण कर पौराणिक भीमगोड़ा कुंड का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भीमगोड़ा कुंड की प्राचीनता, धार्मिक महत्ता और ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन एवं बेहतर रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने एचआरडीए के सचिव प्रत्यूष सिंह को कुंड के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण की योजना एवं डिजाइन को आवश्यक अनुमोदन के बाद तत्काल कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कुंड की सफाई एवं जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था, सीढ़ियों के सुधार, क्षतिग्रस्त पत्थरों को बदलने तथा रेलिंग एवं अन्य संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने को कहा। साथ ही आकर्षक प्रवेश द्वार बनाने, परिसर में स्थित मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संरचनाओं का सौंदर्यीकरण तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने आसपास के भवनों के अग्रभाग (फसाड) को निर्धारित थीम के अनुरूप विकसित करने को कहा। उन्होंने कुंड के प्रवेश द्वार के समीप ऑटो एवं ई-रिक्शा की अनियोजित पार्किंग पर रोक लगाने तथा इनके लिए अन्य उपयुक्त स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त रखने और बेतरतीब निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी सोनिका ने मंगलवार को देर सायं तक कुंभ मेला-2027 से जुड़े विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मेलाधिकारी ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में कुंभ मेला-2027 के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण कर नसमतलीकरण कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा इसके बाद सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों की स्थापना एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ

मेला शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेला एवं अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा तथा आकस्मिक एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त रखने तथा वैंडिंग जोन को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने निर्माणाधीन एडमिन रोड की प्रगति का जायजा लेते हुए कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाटों के सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के ठोस प्रबंध करने तथा आगंतुकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। आस्था पथ से संबंधित कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने दूधाधारी चौक-भूपतवाला क्षेत्र का भ्रमण कर कुंभ मेला-2027 के तहत चल रहे निर्माण कार्यों एवं प्रस्तावित योजनाओं की भी पड़ताल की। उन्होंने कुंभ मेला मद से दूधाधारी चौक से ज्वालापुर तक प्रस्तावित सड़क नवीनीकरण कार्य के प्रारंभिक चरण की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन में साधु-संतों, प्रबुद्धजनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों तथा अन्य सभी हितबद्ध लोगों के सुझावों को ध्यान में

रखा जाए। उन्होंने सड़क परियोजना में निर्धारित स्थानों पर फुटपाथ एवं रेलिंग के निर्माण, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप कार्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण एवं फसाड से संबंधित कार्यों को भी योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने को कहा। साथ ही स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर पार्किंग एवं शौचालयों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेला-2027 से जुड़े सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा में परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

इस दौरान अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, एचआरडीए के सचिव प्रत्यूष सिंह, उप मेलाधिकारी मनजीत सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी.पी. सिंह, अधिशासी अभियंता योगेश कुमार, टेक्निकल सेल के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार, यूपीडीसीसी के परियोजना प्रबंधक सुमित मलवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कनखल में आठ घंटे पानी को तरसे 25 हजार लोग

हरिद्वार । कनखल क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन मरम्मत के चलते बुधवार को करीब 25 हजार आबादी को हृद्द1दृद्द घंटे तक पानी की किल्लत से जूझना पड़ा। सुबह 10 बजे जलापूर्ति बंद होने से लोगों को पेयजल के साथ घरेलू कामकाज पूरा करने में परेशानी हुई। मरम्मत काम के लिए क्षेत्र के पांच पंपिंग स्टेशनों से पानी की सप्लाई को बंद किया गया था। वहीं देर शाम मरम्मत काम पूरा होने के बाद पानी की सप्लाई सुचारु हो सकी।

उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुधवार को कनखल के दादू बाग क्षेत्र में पानी की मुख्य लाइन की मरम्मत का काम किया। इस दौरान क्षेत्र के पांच पंपिंग स्टेशनों बैरागी कैंप एक, बैरागी कैंप दो, ज्ञान लोक कॉलोनी, भगवंत पुरम और लोक सेवा आयोग से पानी की सप्लाई बाधित रही। पानी की सप्लाई बंद होने के बाद कर्मचारियों ने मुख्य पाइपलाइन में लीकेज को सही करने के लिए वेल्लिंग का काम शुरू किया। मौके पर पुरानी पाइप लाइन के साथ नई पाइपलाइन को इंटर कनेक्शन करने का काम किया गया। जल संस्थान की टीम ने दिन भर पाइपलाइन की मरम्मत का काम किया। मरम्मत काम पूरा होने में आठ घंटे का समय लग गया।

ब्रिक्स सम्मेलन से भारत का विश्व को शांति का संदेश

सौरभ वार्धणेय

पूरा विश्व इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें भारत के नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल राष्ट्रीयता की एक कूटनीतिक बैठक भर नहीं है। यह सम्मेलन बदलती हुई विश्व व्यवस्था, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता, युद्धों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और विकासशील देशों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच भारत की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडप में होने वाले 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बार उसका केंद्रीय विषय है (बिल्डिंग फॉर रेसिलिएंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) अर्थात् लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। भारत ने अपनी अध्यक्षता को ह्यूमैनिटी फर्स्ट की सोच से जोड़ते हुए ब्रिक्स को अधिक व्यावहारिक और

विकासोन्मुख मंच बनाने पर जोर दिया है। यही इस सम्मेलन से भारत का पहला और सबसे बड़ा संदेश है—विश्व राजनीति को टकराव से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक हिस्से संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं। यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ब्रिक्स का मंच भारत को यह संदेश देने का अवसर देता है कि अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय हितों वाले देश भी संवाद और सहयोग के माध्यम से साझा समस्याओं पर काम कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति का मूल स्वर न तो किसी एक शक्ति-गुट के साथ खड़ा होना है और न किसी दूसरे गुट के विरोध में

खड़ा होना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। यही रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनती दिखाई दे रही है। ब्रिक्स अब केवल पांच देशों का आर्थिक समूह नहीं रह गया है। इसके विस्तार ने इसे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है। भारत इस मंच के माध्यम से ग्लोबल साउथ की उस आवाज को मजबूती देना चाहता है, जो लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की वास्तविक आर्थिक और जनसंख्या-आधारित ताकत के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल लगातार उठता रहा है। भारत का संदेश स्पष्ट है—21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था 20वीं सदी की शक्ति-संरचना के आधार पर नहीं चल सकती। विश्व अर्थव्यवस्था में उभरती

अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक संस्थाओं में भी उनकी आवाज और भागीदारी बढ़नी चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सहयोग भी होगा। भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। भारत की अध्यक्षता में व्यापार मंत्रियों की बैठकों में भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विविध बनाने तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। भारत का अनुभव बताता है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विशेषकर डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और तकनीक आधारित सेवाएं विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं।

इसलिए ब्रिक्स के मंच से भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि तकनीक केवल विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। भारत आज दुनिया के सामने अपनी डिजिटल क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल भुगतान को आम नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि ब्रिक्स देश डिजिटल भुगतान, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। यह भारत की उस सोच से मेल

खाता है जिसमें तकनीक का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि आम आदमी का सशक्तीकरण भी है। नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भारत-चीन संबंध भी है। चीन की भागीदारी इस सम्मेलन को रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद हाल के वर्षों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह चीन के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं से समझौता न करे। यही भारतीय कूटनीति की परीक्षा है—प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग और मतभेदों के बीच संवाद। भारत यह संदेश देना चाहता है कि किसी देश के साथ आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। ब्रिक्स में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं भारत के अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं।

भारत की यही बहुस्तरीय कूटनीति उसे अन्य देशों से अलग करती है। नई दिल्ली किसी एक ध्रुव की राजनीति का हिस्सा बनने के बजाय अनेक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहती है।

यह संदेश भी महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश की विदेश नीति की छाया नहीं है। भारत अपने हितों के आधार पर अमेरिका के साथ भी संबंध रख सकता है, रूस के साथ भी और चीन के साथ भी संवाद कर सकता है। विश्व में युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने का सीधा प्रभाव ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। तेल, गैस, उर्वरक, अनाज और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने पर सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को होता है। ब्रिक्स के मंच से भारत ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को सामूहिक वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपदा-रोधी क्षमता तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना शामिल है। भारत का संदेश होना चाहिए कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भू-राजनीतिक संघर्षों का अनावश्यक शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के सामने चुनौती है। बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, समुद्री स्तर में वृद्धि और बदलते मौसम का प्रभाव गरीब और विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है। भारत की अध्यक्षता में सतत विकास और लचीली अर्थव्यवस्था पर जोर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का संदेश यह होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देशों के विकास के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। विकसित देशों को वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण में विकासशील देशों की मदद करनी

चाहिए। भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कठोर और साझा वैश्विक कार्रवाई की वकालत करता रहा है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसका नेटवर्क सीमाओं से परे काम करता है और आधुनिक तकनीक तथा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करता है। ब्रिक्स देशों के बीच आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध और आर्थिक अपराधों से मुकाबले में सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत है। भारत आर्थिक अपराधियों और सीमा पार वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी पहल कर रहा है। नई दिल्ली में दुनिया के प्रमुख उभरते देशों के नेताओं का जुटना अपने आप में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत ब्रिक्स को केवल राजधानी-केंद्रित कूटनीतिक मंच के बजाय व्यापक जनभागीदारी और विकास के मंच के रूप में देख रहा है। यह भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वाली व्यापक सोच के साथ भी जुड़ता है। असली सफलता घोषणाओं में नहीं, परिणामों में हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता केवल संयुक्त घोषणा या बड़े-बड़े वक्तव्यों से नहीं मापी जा सकती। नई दिल्ली में आयोजित होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन भारत की विदेश नीति के उस संतुलित स्वरूप को दुनिया के सामने रखने का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय हित, वैश्विक सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता तीनों साथ चलते हैं। भारत दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि नई वैश्विक व्यवस्था किसी एक देश के प्रभुत्व पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी क्षेत्रों, सभी सभ्यताओं और सभी विकास स्तर वाले देशों की भागीदारी होनी चाहिए। भारत यह भी स्पष्ट कर सकता है कि ब्रिक्स किसी देश या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ गठबंधन नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का मंच है। यही दृष्टिकोण भारत को एक पुल की भूमिका देता है—पूर्व और पश्चिम के बीच, विकसित और विकासशील देशों के बीच तथा प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच। नई दिल्ली से दुनिया को यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण संदेश जाना चाहिए तो वह यही है—संघर्ष के स्थान पर संवाद, वर्चस्व के स्थान पर साझेदारी और संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के स्थान पर मानवता के व्यापक हितों को प्राथमिकता दी जाए।

भारत के लिए ब्रिक्स की मेजबानी केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक परिपक्वता, आर्थिक क्षमता और वैश्विक नेतृत्व की परीक्षा भी है। यदि भारत इस सम्मेलन को ठोस आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और मानवीय सहयोग के परिणामों से जोड़ने में सफल होता है, तो नई दिल्ली से निकला संदेश केवल ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहेगा।



उत्तराखण्ड शासन

“भारत रत्न”

पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त



(10 सितम्बर 1887 - 7 मार्च 1961)

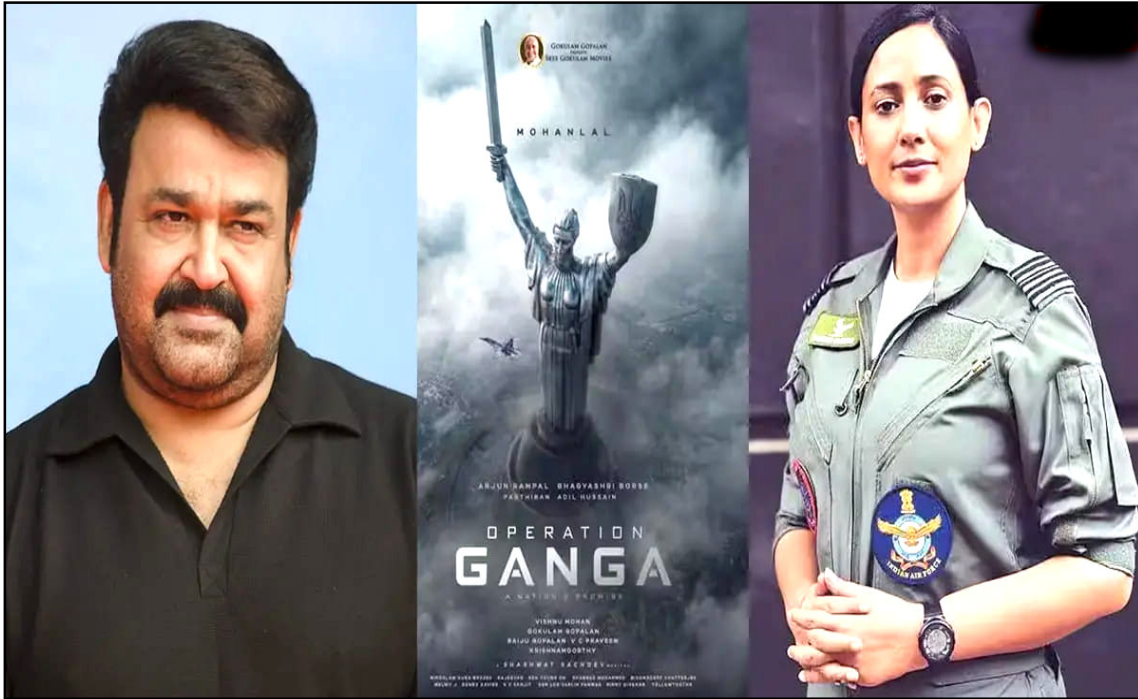
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
एवं कुशल प्रशासक की जयंती
पर

उत्तराखण्ड वासियों
की ओर से शत शत नमन

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarakhandinformation.gov.in | ✉ DIPR_UK | 📞 UttarakhandDIPR | 📺 UttarakhandDIPR

मोहनलाल अब ऑपरेशन गंगा से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक



मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट 'एल367' के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी गई है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए फिल्म का नाम 'ऑपरेशन गंगा' घोषित किया। विष्णु मोहन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर मोहनलाल के प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्सुकता थी।

फिल्म का निर्माण श्री गोकुलम मूवीज के बैनर तले गोकुलम गोपालन कर रहे हैं।

आधिकारिक नाम की घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसमें मलयालम सिनेमा के साथ हिंदी सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिभा को शामिल किया गया है।

फिल्म का नाम भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक बड़े बचाव अभियान 'ऑपरेशन गंगा' पर आधारित है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, विशेष रूप से छात्र, यूक्रेन में फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित

भारत वापस लाने के लिए सरकार ने

विशेष अभियान चलाया था।

फिल्म इसी महत्वपूर्ण अभियान से प्रेरित कहानी के जरिए दर्शकों को उस समय की परिस्थितियों और भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के प्रयासों से रूबरू कराएगी। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म में इस बड़े अभियान को प्रभावशाली और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

'ऑपरेशन गंगा' का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार विष्णु मोहन कर रहे हैं। वह मलयालम फिल्म उद्योग से जुड़े हैं और राजनीतिक नाटक पर आधारित फिल्म 'मेप्पडियान' के निर्देशन के लिए पहचाने जाते हैं। वर्ष 2022 में इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। फिल्म का निर्माण गोकुलम गोपालन कर रहे हैं। बैजू गोपालन और वी. सी. प्रवीण सह-निर्माता हैं, जबकि कृष्णमूर्ति कार्यकारी निर्माता की जिम्मेदारी संभाल

रहे हैं।

फिल्म में मोहनलाल के साथ हिंदी सिनेमा के अभिनेता अर्जुन रामपाल, आदिल हुसैन और भाग्यश्री भोरसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। अभिनेता पार्थिवन भी फिल्म के कलाकारों का हिस्सा हैं।

फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी खास है। 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' के लिए चर्चित छायाकार मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक फिल्म की छायांकन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संगीत शाश्वत सचदेव तैयार कर रहे हैं, जबकि चर्चित कार्रवाई निर्देशक सी यंग ओह फिल्म के रोमांचक दृश्यों को आकार देंगे।

'ऑपरेशन गंगा' की आधिकारिक घोषणा के बाद मोहनलाल के प्रशंसकों के साथ-साथ भारतीय सिनेमा के दर्शकों की नजर अब फिल्म की अगली जानकारी और प्रदर्शन तिथि पर टिकी है।

'इरुमुडी' ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा, 18 सितंबर को ओटीटी प्रसारण की

रवि तेजा की मुख्य भूमिका और शिवा निर्वाण के निर्देशन में बनी फिल्म 'इरुमुडी' 21 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। भावनात्मक एक्शन ड्रामा कही जा रही इस फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। सिनेमाघरों में मिल रही मजबूत प्रतिक्रिया के बीच अब फिल्म के ओटीटी प्रसारण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

रिपोर्टों के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने 'इरुमुडी' के डिजिटल प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं और फिल्म के ओटीटी प्रसारण के लिए 18 सितंबर, 2026 की तारीख पर चर्चा चल रही है। हालांकि, नेटफ्लिक्स या फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस तारीख की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सिनेमाघरों में फिल्म को मिल रही दर्शकों की



प्रतिक्रिया को देखते हुए निर्माता इसकी प्रदर्शन अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म का डिजिटल प्रसारण तय समय से आगे खिसक सकता है। फिल्म के सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन को देखते हुए इसकी चार सप्ताह की निर्धारित अवधि को छह या आठ सप्ताह तक बढ़ाने पर बातचीत होने की खबर है। यदि ऐसा होता है तो 'इरुमुडी' का डिजिटल प्रसारण अक्टूबर तक टल सकता है। हालांकि, इस संबंध में निर्माताओं या

नेटफ्लिक्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

फिल्म के सिनेमाघरों में लंबे समय तक प्रदर्शन का सीधा फायदा इसके कारोबार को मिल सकता है। दर्शकों की मांग बनी रहने की स्थिति में निर्माता ओटीटी प्रसारण से पहले फिल्म की कमाई को अधिकतम करने की कोशिश कर सकते हैं। रवि तेजा के साथ पहले भी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है। वर्ष 2021 में रिलीज हुई उनकी सफल फिल्म 'कैक' का डिजिटल प्रसारण 29 जनवरी को 'आहा' पर होना तय था। हालांकि, सिनेमाघरों में फिल्म को मिली शानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए इसके डिजिटल प्रसारण को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। इसी पुराने उदाहरण के कारण 'इरुमुडी' के डिजिटल प्रसारण में संभावित देरी की खबर को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फिल्म वास्तव में 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी या इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। दर्शकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

असुर 3 के साथ फिर गहरा होगा खौफनाक हत्याओं का खेल, शुरू हो गई शूटिंग



ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक, अरशद वारसी और बरुन सोबती की असुर अपने तीसरे सीजन के साथ लौटेगी। इसकी शूटिंग मुंबई में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस बार निर्देशन की कमान गौरव शुक्ला संभाल रहे हैं, जिन्होंने सीरीज का निर्माण और लेखन कार्य के किया है। दरअसल, असुर के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इनका निर्देशन ओनी सेन ने किया था, जिन्होंने हालिया रिलीज सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी निर्देशित की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं ने 30 अगस्त से मुंबई में शूटिंग शुरू कर दी है। अगले तीन महीनों में कई शहरों में फिल्मांकन करने की उम्मीद है।

उनका लक्ष्य 2027 के मध्य में जियोहॉटस्टार पर सीरीज का प्रीमियर करना है। अरशद और बरुन अपने निभाए गए किरदारों धनंजय राजपूत और निखिल नायर के रूप में फिर वापसी करेंगे।

रिद्धि डोगरा, अनुप्रिया गोयनका और विशेष बंसल भी लौटेंगे, जबकि नए चेहरों में अहसास चन्ना और श्वेता बसु प्रसाद शामिल होंगी।

असुर का पहला सीजन कोविड के दौरान, साल 2020 में जियो सिनेमा पर प्रसारित हुआ था। इसकी लोकप्रियता के बाद, 2023 में निर्माता दूसरा सी8जन लेकर आए।

इसकी कहानी अच्छाई बनाम बुराई और इंसानी स्वभाव के काले पक्ष की एक गहरी जंग पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि हर अच्छे इंसान के अंदर एक शैतान (असुर) छिपा होता है। खौफनाक हत्याओं और खतरनाक इंसानी दिमाग का खेल तीसरे सीजन को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है।

हुंकार-द रोर का दमदार टीजर जारी, सैयारा के बाद अनीत पड्डा ने दिखाया नया अवतार

सैयारा की वाणी यानी अनीत पड्डा अब एक नए और बिलकुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। अनीत नई ड्रामा सीरीज हुंकार: द रोर में नजर आने वाली हैं, जिसका टीजर जारी किया जा चुका है। यह सीरीज एक ऐसे आरोप के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ताकतवर सिस्टम को सवालियों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। कहानी 17 साल की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अनीत पड्डा निभा रही हैं। मीनू बापजी के नाम से मशहूर जाने-माने कल्ट लीडर सुनील चाकोसी पर एक आरोप लगाती है, जिसके बाद बापजी के खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो जाती है। टीजर से साफ है कि एक आरोप से शुरू होने वाली कहानी जल्दी ही एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है और मामला पुलिस के बाद कोर्ट और मीडिया तक पहुंचता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हुंकार के टीजर में तीन मुख्य किरदार देखने को मिलती हैं और तीनों किरदार एक ही लड़ाई को अलग-अलग तरीके से लड़ रहे हैं। एसीपी जसलीन सिंह सोनी पुलिस की तरफ से यह केस की कमान संभालती हैं। भलेराव एक स्टूडेंटिंग वकील हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जबकि पत्रकार अमिताभ मीडिया के जरिए इस कहानी को कवर करते हैं। इस सीरीज में पुलिस की जांच से लेकर कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया ट्रायल तक सब देखने को मिलेगा और जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, राष्ट्रीय स्तर पर ये केस चर्चा का विषय बन जाता है। इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए, अनीत पड्डा ने अपने फैंस को इस सीरीज के बारे में जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि इसकी शूटिंग सैयारा से पहले ही हो गई थी। टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में अनीत ने लिखा- पेश है एक छोटी सी चीज जिसकी शूटिंग मैंने सैयारा से पहले की थी। हुंकार कुछ समय से मेरे सफर का हिस्सा रही है, और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं इसे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इंसाफ का इंतजार नहीं होगा, बस सच्चाई की हुंकार गूँजेगी। हॉटस्टार स्पेशल: हुंकार - द रोर, 25 सितंबर से सिर्फ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। हुंकार: द रोर का निर्देशन करण डी कपाडिया, नित्या मेहरा और हीराज मरफातिया ने किया है। इस सीरीज में अनीत पड्डा के साथ फ़ातिमा शेख, अर्जुन माथुर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, रघुबीर यादव और राम कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। हुंकार: द रोर का प्रीमियर 25 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

खाना बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, सेहत को होगा फायदा



खाना बनाना एक कला है, जिसमें सिर्फ तेल का इस्तेमाल ही नहीं होता। सही तरीके से खाना बनाकर हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने खाने को और भी सेहतमंद बना सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल स्वाद बढ़ा सकते हैं, बल्कि पोषण भी सुधार सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप रोजमर्रा की रसोई में छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं।

तेल का सही उपयोग करें

खाना बनाते समय तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल से न केवल खाने का स्वाद बिगड़ता है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।

कोशिश करें कि खाना बनाते समय कम तेल का इस्तेमाल करें और उसे बार-बार न गर्म करें। इससे न केवल आपका खाना सेहतमंद रहेगा बल्कि आपके शरीर को अतिरिक्त चर्बी से भी छुटकारा मिलेगा।

सही मात्रा में तेल का उपयोग करने से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में संतुलन बना सकते हैं।

सब्जियों को भूनने का तरीका बदलें

सब्जियों को भूनते समय अक्सर लोग ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाना तला हुआ सा लगने लगता है और उसमें अतिरिक्त कैलोरी शामिल हो जाती है। इसकी बजाय आप सब्जियों को भूनने के लिए थोड़े पानी का उपयोग कर सकते हैं या ऐसे बर्तन में पकाएं जो चिपकता न हो। इससे न केवल कैलोरी कम होगी बल्कि सब्जियों का प्राकृतिक स्वाद भी बना रहेगा।

इस तरह आपका खाना सेहतमंद और स्वादिष्ट बनेगा।

मसालों का सही मिश्रण बनाएं
मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें पौष्टिक भी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी ज्यादा मसाले खाने का स्वाद

बिगाड़ सकते हैं और पाचन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए मसालों का सही मिश्रण बनाना जरूरी है ताकि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी हो।

हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसालों का सही अनुपात मिलाकर इस्तेमाल करने से आपका खाना सेहतमंद बना रहेगा और पाचन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

नमक का सही उपयोग करें

नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए नमक का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है।

खाने में स्वाद लाने के लिए आप सेंधा नमक या काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहत के लिए बेहतर होते हैं और स्वाद में भी अच्छे लगते हैं।

पानी का सही उपयोग करें

खाना बनाते समय पानी का सही उपयोग करना भी अहम होता है।

ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से खाना पतला हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना कम पानी इस्तेमाल करें ताकि आपका खाना पौष्टिक बना रहे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की रसोई को न केवल सेहतमंद बना सकते हैं बल्कि अपने खाने का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं।

घुटनों के दर्द ने मुश्किल कर दिया है जीना? तो अपनाएं ये घरेलू उपाय



घुटनों का दर्द एक आम समस्या हो सकती है और यह आपके दैनिक जीवन को कठिन बना सकती है। यहां कुछ घरेलू उपाय हैं जो घुटनों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं:

गर्म पानी से स्नान:- रोजाना गर्म पानी से नहाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। गर्म पानी के टब में बैठकर घुटनों को उसमें रखें या फिर गर्म पानी की बाल्टी में दोनों पैरों को डालें। इससे घुटनों की सूजन कम होगी और दर्द में आराम मिलेगा।

हल्दी और दूध का सेवन:-

आधा चम्मच हल्दी को एक ग्लास गर्म दूध में मिलाएं और रोजाना सोने से पहले पिएं। हल्दी और दूध में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण घुटनों के दर्द को कम करते हैं।

अदरक और लहसुन का तेल:-

अदरक और लहसुन के ताजे रस को घुटनों पर मसाज करें। इससे दर्द में आराम मिलेगा और घुटनों की सूजन कम होगी।

मसाज और पानी की कंप्रेस:-

घुटनों को आराम देने के लिए उन्हें हल्के हाथ से मसाज करें। इसके साथ ही, ठंडे पानी के कंप्रेस को घुटनों पर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा।

सही आहार:-

स्वस्थ आहार खाने में सहायता मिलती है। विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, और ओमेगा-3 चर्मादार भोजन घुटनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यदि घुटनों का दर्द लंबे समय तक बना रहता है और इन घरेलू उपायों से भी आराम नहीं मिलता है, तो आपको एक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।

फैटी लिवर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 फल



नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर (इन्फ्लेम) से पीड़ित हैं। यह वसा या रक्त लिपिड को कम करने और लिवर को पहले की तरह स्वस्थ करने में मदद कर सकता है।

ब्लूबेरी -ब्लूबेरी एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और लिवर की बीमारियों, विशेष रूप से फैटी लीवर, के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें एंथोसायनिन और फाइबर जैसे खनिज भी मौजूद होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और ग्लूकोज के स्तर में सुधार करने में सक्षम हैं। इन तीनों के स्तर में गड़बड़ी होने से हृदय रोग और लिवर की समस्या पैदा हो सकती है।

अंगूर - अंगूर में रेस्वेराट्रॉल नामक खास तत्व मौजूद होता है, जो फैटी लिवर का खतरा कम करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। अंगूर में बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जो एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण की तरह काम करके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, फैटी लिवर वाले लोग डाइट में अंगूर को शामिल करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें।

सेब - यह फल भी लिवर के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है और यह लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद कर सकता है। फैटी लिवर का जोखिम कम करने में भी इस फल का सेवन काफी मदद कर सकता है।

फैटी लिवर की बीमारी लिवर की कोशिकाओं में ज्यादा फैट जमा होने की वजह से होती है और इसमें लिवर सही तरह से काम करना बंद कर देता है। अगर समय रहते इसके उपचार पर ध्यान न दिया जाए तो यह लिवर फेल होने या लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। स्वस्थ जीवनशैली और डाइट में फाइबर युक्त फलों को शामिल करके इस बीमारी के खतरे को प्राकृतिक रूप से कम किया जा सकता है।

चकोतरा - खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर यह फल फैटी लिवर के प्रभाव को कम करने में काफी मदद कर सकता

है। चकोतरा में मौजूद विटामिन- सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स आपके लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं। यही नहीं, इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर की वसा को कम करने का काम करता है। चकोतरा के सेवन से ये 5 फायदे भी मिल सकते हैं।

एवोकाडो - फैटी लिवर से निपटने के लिए कई डॉक्टर मरीज की डाइट में एवोकाडो को शामिल करने की सलाह देते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल से भरपूर एवोकाडो को खाने का सुझाव उन लोगों के लिए दिया जाता है, जो

क्या आपका भी बार बार करता है मीठा खाने का मन, तो जान लें इसके नुकसान

अक्सर किसी खास मौके पर मीठे के बिना सेलिब्रेशन अधूरा-अधूरा सा लगता है। बहुत से लोग तो मीठा खाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। उन्हें मीठा काफी पसंद होता है। हालांकि, इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। फलों, सब्जियों, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरल शुगर पाई जाती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होती है लेकिन आर्टिफिशियल शुगर या एडेड शुगर से मोटापा, डायबिटीज और दिल की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा मीठा सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। 2014 के पब्लिश एक स्टडी में बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा चीनी खाने से मोटापा, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। पिछले कुछ अध्ययनों में भी पता चला है कि एडेड शुगर शरीर के नेचुरल ब्लड शुगर के लेवल बढ़ा देती है। इससे कई लोग प्री-डायबिटिक भी हो जाते हैं।

शुगर क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें - अपनी डाइट में मीठा सीमित मात्रा में रह रखें। मीठा खाने वालों के लिए इसे कंट्रोल करना अतना आसान नहीं होता है। उन्हें बार-बार मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है। जिसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ उपाय बताए हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि आंत के बैक्टीरिया में असंतुलन से मीठा खाने की क्रेविंग होती है। जब हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसे में मीठे की क्रेविंग कम करने के लिए हाई फाइबर फूड्स फायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि ये हेलदी गट माइक्रोबायोम को बढ़ावा देकर क्रेविंग को कम करते हैं।

शुगर क्रेविंग कंट्रोल करने क्या खाएं

रिफाईंड शुगर की बजाय फलों के सेवन से पेट के माइक्रोबायोम मैनेज होते हैं। इससे क्रेविंग कम करने में मदद मिलती है। हाई फाइबर वाले फलों में सेब, नाशपाती, केला, संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, आलू बुखारा, आम, तरबूज और अमरूद का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अनुसार, हर दिन 6 चम्मच से कम चीनी का सेवन करने और लाइफस्टाइल को सही रखने से इसके खतरे को कम किया जा सकता है।



कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्माण स्थलों का किया स्थलीय निरीक्षण

हरिद्वार । कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को धरातल पर परखने के लिए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन श्री आनंद वर्द्धन ने गुरुवार को हरिद्वार में विभिन्न निर्माण स्थलों का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ अरबेनिया वाहन में बैठकर रोड़ी-बेलवाला से लेकर रोशनाबाद होते हुए कनखल-दक्षद्वीप-बैरागी कैंप से लेकर सीसीआर टावर तक एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक पहुंचकर मौके पर चल रहे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, तकनीकी पहलुओं, उपयोगिता तथा निर्धारित समयसीमा की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ ही मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित सुविधाओं और व्यवस्थाओं को भी मौके पर परखा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कुंभ मेला-2027 से संबंधित सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित समीक्षा और स्थलीय निगरानी के साथ उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिनकी गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कार्यों में आने वाली बाधाओं की तत्काल पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित करने तथा विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने के



निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला-2027 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सड़क, पुल, पैदल मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य, पार्किंग, प्रशासनिक एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य समय से पूरे होना आवश्यक है। निर्माण के दौरान आमजन और स्थानीय नागरिकों की सुविधा, यातायात व्यवस्था तथा सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने रोड़ी-बेलवाला क्षेत्र में उत्तराखण्ड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की प्रशासनिक मार्ग परियोजना तथा रोड़ी-बेलवाला एवं हरकी पैड़ी क्षेत्र की पुनर्विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा

और सुरक्षा के अनुरूप उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियों एवं विकसित व्यवस्थाओं के पांच वर्ष की अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद उनके स्थायी रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग अथवा निकाय को सौंपने की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेलाधिकारी को इस संबंध में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था का औपचारिक मसौदा शासन की स्वीकृति के लिए भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने हाथीपुल से अलकनंदा के मध्य घाटों के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों का भी जायजा लिया। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग और चेन की समुचित व्यवस्था करने तथा पैदल

आवागमन को सुगम बनाने के निर्देश दिए। प्रशासनिक मार्ग निर्माण के लिए शासन द्वारा 4325.14 लाख तथा हरकी पैड़ी रिवाइलाइजेशन कार्य के लिए 6677.21 लाख की धनराशि स्वीकृत है। ऋषिकुल क्षेत्र में मुख्य सचिव ने ओल्ड दिल्ली-नीतिपास मार्ग के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यातायात एवं स्थानीय आवागमन को ध्यान में रखते हुए कार्य के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सड़क किनारे विकसित किए जा रहे फुटपाथ एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधरोपण कर हरियाली विकसित करने पर जोर दिया। दूधधारी चौक से ज्वालापुर तक के हिस्से सहित लोक निर्माण विभाग के अधीन शहर की अन्य आंतरिक सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2164.49 लाख की धनराशि स्वीकृत है। इसके बाद मुख्य सचिव ने शिवमूर्ति चौक, शंकर आश्रम चौक तथा भगत सिंह चौक से विल्केश्वर तक चौराहों के सुधार एवं पैडेस्ट्रियन फुटपाथ कार्य का निरीक्षण किया। 683.60 लाख की लागत वाले इस कार्य में पैदल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित आवागमन और यातायात के सुचारु संचालन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रोशनाबाद में मुख्य सचिव ने 251.98 लाख की लागत से निर्माणाधीन डूंग वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात दक्षद्वीप स्थित बैरागी क्षेत्र में निर्माणाधीन 60 मीटर स्पान के पुल का निरीक्षण किया। इस परियोजना के लिए 1246.09 लाख की धनराशि स्वीकृत है। उन्होंने पुल निर्माण की प्रगति एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी लेते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सीसीआर-2 भवन का भी निरीक्षण किया और कुंभ मेला शुरू होने से पहले भवन को तैयार करने के लिए कार्य में तेजी लाने तथा आवश्यकता के अनुसार दिन-रात कार्य कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने डाम कोठी में कुंभ मेला एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार निर्माण कार्यों और अन्य तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को पर्याप्त मानव संसाधन एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने कुंभ मेला के निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच के लिए नियुक्त टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लि., क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया प्रा. लि. तथा ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्रा. लि. के टीम लीडर्स से गुणवत्ता जांच की प्रगति की जानकारी ली।

आईआईटी रुड़की ने विकसित किया स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैट्रेज, घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने में सहायक



रुड़की । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) के शोधकर्ताओं ने इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएनएसटी), मोहाली के सहयोग से एक स्मार्ट, स्व-संचालित इलेक्ट्रॉनिक बैट्रेज विकसित किया है, जो प्राकृतिक शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जो घाव भरने की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए बैटरी, तार या किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इस तकनीक को 3 डी मोनोलिथिक इंटोग्रेटेड डाइपोलर और आयनिक फाइब्रस आर्किटेक्चरल स्कैफोल्ड कहा जाता है। यह तकनीक उस समय उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत उत्तेजना में परिवर्तित करती है, जब लचीली सामग्री प्राकृतिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान खिंचती है। सरल शब्दों में, शरीर की गतिविधियाँ स्वयं बैट्रेज को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता कर सकती हैं।

घाव भरना एक जटिल प्रक्रिया है और त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर ऊतक की मरम्मत के दौरान कोशिकाओं को दिशा देने वाले प्राकृतिक विद्युत संकेत बाधित

हो सकते हैं। 3 डी एमआईडीएस को घाव के स्थान पर विद्युत उत्तेजना प्रदान करने के साथ-साथ एक लचीली, वायु-संचार योग्य संरचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो घाव से निकलने वाले द्रव के प्रबंधन में भी सहायता करती है। यह स्कैफोल्ड अपनी मूल लंबाई

की लगभग 800 प्रतिशत तक खिंच सकता है, जिससे यह शरीर की गतिविधियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकता है। यह तकनीक एकल त्रि-आयामी रेशेदार संरचना के भीतर विद्युत रूप से सक्रिय नैनोफाइबर और आयनिक रूप से प्रवाहकीय नेटवर्क को एकीकृत करती है। जब सामग्री को खींचा जाता है, तो ये घटक मिलकर विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। इसकी छिद्रयुक्त संरचना वायु-संचार और घाव से निकलने वाले द्रव के प्रबंधन में भी सहायता करती है। 'अनुसंधान का वास्तविक मूल्य समाज से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान में योगदान देने की इसकी क्षमता में निहित है। यह कार्य इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि उन्नत सामग्रियों और अंतर्विषयक अनुसंधान को किस प्रकार व्यावहारिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के समाधान की दिशा में केंद्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके घाव देखभाल की तकनीक को ऊर्जा प्रदान करने का विचार अभिनव होने के साथ-साथ संभावित रूप से महत्वपूर्ण भी है, विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सरल, लचीले और

स्व-संचालित समाधान लाभकारी हो सकते हैं। 'हम मौजूदा विद्युत-आधारित घाव भरने वाली कई प्रणालियों की एक मूलभूत सीमा को दूर करना चाहते थे, जिसमें बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। 3 डी एमआईडीएस के साथ, शरीर की गतिविधियाँ स्वयं विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। साथ ही, यह ड्रेसिंग लचीली, वायु-संचार योग्य है और घाव से निकलने वाले द्रव के प्रबंधन में सक्षम है। हमारे परिणाम उत्साहजनक हैं और संकेत देते हैं कि यह दृष्टिकोण भविष्य में अधिक सुविधाजनक और स्व-संचालित घाव देखभाल तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है,' कहा प्रो. कौशिक पारिदा, प्रधान अन्वेषक, आईआईटी रुड़की ने। इस तकनीक का मूल्यांकन प्रयोगशाला और पशु अध्ययनों के माध्यम से किया गया है, जिसमें उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रयोगशाला परीक्षणों में, 3क-डब्ल्यू ने नियंत्रण परिस्थितियों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक कोशिका प्रसार और 2.5 गुना अधिक कोशिका प्रवासन प्रदर्शित किया, जो ऊतक की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण दो प्रक्रियाएँ हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी परीक्षण किया कि क्या ड्रेसिंग प्राकृतिक शारीरिक गतिविधियों से विद्युत आउटपुट उत्पन्न कर सकती है। स्वतंत्र रूप से गति करने वाले चूहों के घावों पर लगाए जाने पर, ड्रेसिंग ने बिना किसी बाहरी यांत्रिक उत्तेजना के, चूहों की गतिविधियों के दौरान लगातार विद्युत आउटपुट उत्पन्न किया।

बैंक हड़ताल से उपभोक्ताओं को हुई परेशानी

हरिद्वार । बैंककर्मियों की हड़ताल से शुक्रवार को उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब सोमवार तक इंतजार करना होगा। कई उपभोक्ताओं को हड़ताल की जानकारी नहीं होने पर बैंक से मायूस होकर लौटना पड़ा। उपभोक्ताओं का कहना है कि शुक्रवार को हड़ताल नहीं होनी चाहिए, इससे आगे के दिन भी बैंक बंद होने से अधिक परेशानी होती है। सबसे अधिक बुजुर्ग और महिलाओं को परेशानी हुई। बैंक बंद होने से करोड़ों रुपयों के लेनदेन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वहीं बैंककर्मियों का कहना है कि हड़ताल से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। 28, 29, 30 सितंबर को भी हड़ताल की संभावना है। सुनील बख्शी ने बताया कि बैंक में पेंशन संबंधी किसी कार्य से आए थे। यहाँ आकर पता लगा हड़ताल है। अब शनिवार, रविवार भी छुट्टी रहेगी। सोमवार को बैंक खुलेगा तब बात होगी। तिलक राज ने बताया कि पहले घाट होता तो नहीं आते। सरकार कहती है सरकारी बैंक में खाता खुलवाओ। सबसे अधिक हड़ताल और छुट्टियाँ भी सरकारी बैंक में ही होती हैं। इससे परेशानी होती है। सरकार को जनहित में कार्य करना चाहिए। नया खाता खुलवाया था कॉपी लेने आए थे लेकिन बैंक बंद है। सिडकुल कंपनी में कार्यरत गीता ने बताया कि एक दिन की छुट्टी लेकर सोचा था बैंक का काम निपटा लेंगे लेकिन अब तीन दिन बाद फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जगजीतपुर फुटबॉल ग्राउंड निवासी सुमित चावला ने बताया कि उनका खाता दादूबाग स्थित बैंक में है। घर से 2 किमी की दूरी पर बैंक है। दुकान छोड़कर बैंक में पैसे जमा करने आए थे लेकिन हड़ताल होने से पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। सोमवार को बता रहे खुलेगा। अमृत लाल ने बताया कि लोन के लिए आवेदन किया था। उसी के बारे में मालूम करना था। हड़ताल से दोबारा आना पड़ेगा। इससे काम भी प्रभावित होता है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

सम्पादक: अवनीश कुमार, मो० 9410553400

ई-मेल: liveskgnews@gmail.com

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)

सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं है।